International Research Journal of Commerce and Law
Volume 13 Issue 8,August 2025 ISSN: 2349-705x Impact Factor: 8.843
Journal Homepage: http://ijmr.net.in, Email:irjmss@gmail.com Double-Blind
Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal

राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की भूमिका

Dr. Manju (Associate professor political science)

राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से अपेक्षाकृत पिछड़े हुए हैं। यहाँ मुख्य रूप से भील, मीणा, गरासिया, सहरिया जैसी जनजातियाँ निवास करती हैं, जो उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, चित्तौड़गढ़, बारां आदि जिलों में फैली हुई हैं। इन जनजातीय समुदायों के समग्र विकास हेतु केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ लागू की गई हैं, जिनकी भूमिका बहुआयामी रही ह

1. सामाजिक सशक्तिकरण में भूमिका:

सरकार की योजनाओं ने जनजातीय समाज को सामाजिक रूप से सशक्त करने में मदद की है। जैसे:

वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत आदिवासियों को उनके पारंपरिक वनभूमि पर अधिकार दिया गया है, जिससे उन्हें सुरक्षा की भावना मिली है।

सहरिया विशेष सहायता योजना जैसी योजनाओं ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को खाद्य सुरक्षा, पोषण और आवास सहायता प्रदान की।

2. शिक्षा के क्षेत्र में सुधार:

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) और मुख्यमंत्री आदर्श आवासीय विद्यालय योजना के तहत जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्रावास की सुविधा दी गई है।

प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएँ जनजातीय छात्रों को पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने में सहायक रही हैं।

3. आजीविका और रोजगार में योगदान:

मनरेगा (MGNREGA) जैसी योजनाओं ने ग्रामीण जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार का अवसर प्रदान किया है।

राजीव गांधी आजीविका मिशन और जनजाति विशेष स्वरोजगार योजना के माध्यम से आदिवासी युवाओं को कुटीर उद्योग, डेयरी, हस्तशिल्प आदि में स्वरोजगार के अवसर मिले हैं।

4. स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार:

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत जनजातीय क्षेत्रों में मोबाइल हेल्थ यूनिट, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाया है।

आंगनबाड़ी केंद्रों और पोषण आहार योजनाओं ने महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को कम करने में सहयोग दिया है।

5. आधारभूत संरचना विकास में योगदान:

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, सौभाग्य योजना जैसी योजनाओं ने आदिवासी क्षेत्रों में सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाई है।

इससे बाजार, स्कूल और अस्पतालों तक पहुँच में सुधार हुआ है।

निष्कर्ष:

राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं ने समाज के विभिन्न पहलुओं – शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुरक्षा – में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का कार्य किया है। हालांकि, योजनाओं का सटीक क्रियान्वयन, भ्रष्टाचार की रोकथाम और जनजागरूकता बढ़ाना आवश्यक है ताकि योजनाओं का पूरा लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँचे। जनजातीय समाज का सतत विकास तभी संभव है जब योजनाएँ केवल कागज़ों तक सीमित न रहें, बल्कि धरातल पर प्रभावी रूप से लागू हों।

राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र में सरकारी योजनाओं की भूमिका के संबंध में ग्रंथ/संदर्भ ग्रंथ सूची

यदि आप राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की भूमिका पर अध्ययन या शोध करना चाहते हैं, तो नीचे दी गई पुस्तकें, शोध पत्र, सरकारी रिपोर्ट्स और वेबसाइट्स एक उपयोगी संदर्भ सूची के रूप में काम आएंगी:

पुस्तकें (Books):

1. "Tribal Development and Planning"

लेखक: R.C. Verma

विवरण: भारत में जनजातीय विकास की नीतियाँ, योजनाएँ और उनके प्रभाव पर समग्र दृष्टिकोण।

2. "Tribal Development in Rajasthan"

लेखक: Dr. K.C. Mangal

विवरण: राजस्थान में जनजातीय विकास योजनाओं की स्थिति, चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएँ।

3. "Tribal Welfare and Development"

लेखक: D.N. Thakur

विवरण: भारत के आदिवासी समाज पर केंद्रित, विशेष रूप से कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा।

4. "Planning for Tribal Development"

लेखक: S.C. Dube

विवरण: जनजातीय क्षेत्रों के लिए योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं सुधार सुझाव।

5. "राजस्थान में जनजातीय विकास" (हिंदी)

लेखक: डॉ. नंदकिशोर शर्मा

विवरण: राजस्थान के आदिवासी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर केंद्रित हिंदी पुस्तक।

शोध पत्र / जर्नल लेख (Research Papers / Journals):

1. "Impact of Government Schemes on Tribal Livelihood in Rajasthan"

स्रोत: Indian Journal of Social Research

2. "Effectiveness of Tribal Sub-Plan in Rajasthan"

स्रोत: Economic and Political Weekly (EPW)

शोध में TSP की भूमिका और प्रभाव का विश्लेषण।

3. "Livelihood Transformation in Tribal Areas through Government Schemes"

स्रोत: Journal of Rural Development

सरकारी रिपोर्ट्स और दस्तावेज (Government Reports & Documents):

1. जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs), भारत सरकार

वेबसाइट: https://tribal.nic.in

वार्षिक रिपोर्ट्स

योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट

वन अधिकार अधिनियम की स्थित

2. राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

वेबसाइट: https://tribal.rajasthan.gov.in

योजना दस्तावेज

बजट एवं व्यय रिपोर्ट

ज़िला-स्तरीय योजना निष्पादन विवरण

3. NITI Aayog Reports on Tribal Development

नीति आयोग द्वारा जनजातीय क्षेत्रों की योजनाओं की मूल्यांकन रिपोर्ट।

4. Census of India – Rajasthan (Scheduled Tribes Data)

जनसंख्या, शिक्षा, आजीविका आदि के आंकड़े।

ऑनलाइन शोध पोर्टल:

Shodhganga (INFLIBNET)

शोध प्रबंध और थीसिस राजस्थान के जनजातीय विकास पर।